भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन रुग्ण इकाइयां

2074. **श्री राम सिंह राठवा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाइयों के रुग्ण होने के आंतरिक कारणों का पता नहीं लगाया गया है ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन कितनी रुग्ण इकाइयां थीं और उन पर कितनी धनराशि ऋण के रूप में बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक एककों की रुग्णता के कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग होते हैं । सहायता प्राप्त एककों पर अनुवर्ती कार्रवाई और मानीटरिंग के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, प्रारम्भिक रुग्णता के आन्तरिक कारणों का पता लगाता है, जो सामान्यतः प्रबंधकीय कमजोरियों, समय और लागत में वृद्धि, पुरानी प्रौद्योगिकी, श्रमिक समस्याओं आदि से सम्बद्ध होती है । आगे और खराबी से बचने के लिये और एकक की अर्थक्षमता को पुनः स्थापित करने के लिये विभिन्न उपाय किये जाते हैं ।

(ख) मार्च, 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पोर्ट-फोलियो में 375 रुग्ण एकक शामिल थे और इनमें कुल 1344 करोड़ रुपये की बकाया रकम ग्रस्त थी ।

विदेशी ऋणों की अधिकतम सीमानिर्धारित करना

2075. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सरकार देश की विदेशी ऋण देयताओं के विषय में सचेत है और देश की ऋण ग्रस्तता के स्तर और ऋण शोधन प्रभार के संभाव्य बोझ पर निरंतर निगाह रखती है । विदेशी ऋण हेतु समझौता करते समय वह बात हमेशा ध्यान में रखी जाती हैं कि देश का ऋण बोझ और ऋण शोधन देयतायें इस प्रकार के ऋणों का शोधन करते समय अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हों । सरकार ने अल्पावधि स्थिरीकरण सहित दीर्घावधि पुर्ननिर्माण का लक्ष्य रखते हुए आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम पहले ही प्रारंभ कर दिया है । इन सुधारों से देश को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारी निर्यात अर्जन क्षमता सहित हमारी विकास प्रक्रिया पुनर्जीवित होगी जिससे ऋणों की वापसी अदायगी की हमारी क्षमता बढ़ सकेगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऋण शोधन प्रभार का बोझ इस प्रकार के ऋणों का शोधन करते समय अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक नहीं होगा ।

सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये कार्रवाई योजना

2076. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कारवाई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्रवाई योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कहां तक लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य सहकारी बैंकों (एस० सी० बी०) को जिला-वार कार्य योजनायें तैयार करने को कहा है जिसे राज्य कार्य योजनाओं में मिला दिया जाएगा । ऐसे राज्य कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन से ऐसा आधार तैयार होगा जिसपर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डी०सी०सी०बी) और सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा । ये योजनायें सहकारी बैंकों के ढांचे की कमजोरियों की पहचान पर ध्यान केन्द्रित करेंगी और ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आत्म-निर्भर होने के लिए सहकारी प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय करेंगी ।

विदेशी ऋणों का चुकाया जाना

2077. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री 22 फरवरी, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 56 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ऋणों पर प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक देश से ली गई धन-राशि को कब तक लौटाना होगा ;

(ग) क्या पिछली या वर्तमान सरकार ने उक्त ऋणों को चुकाने के लिए कोई प्रयास किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऋण की कितनी राशि लौटाई जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) (क) : 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय निक्षेपों सहित विदेशी ऋण पर अदा की गयी राशि क्रमशः 3668 मिलियन अमरीकी डालर और 3725 मिलियन अमरीकी डालर थी ।

(ख) प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार परस्पर स्वीकार्य निश्चित तारीखों को ऋणों की वापसी अदायगी की जा रही है । वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है । सरकारी खाते में और गैर-सरकारी खाते में ऋणों के बारे में प्रत्येक ऋण की शर्तों का ब्यौरा वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित विदेशी सहायता ब्राउशर में दिया गया है। ब्राउशर की एक प्रति पहले ही सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ग) प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार निश्चित तारीखों को ऋणों की वापसी अदायगी की जा रही है । सरकार ने कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और विदेशी वित्तपोषण पर निर्भरता में कमी करने के लिए निर्यातों में तेजी लाने तथा अदृश्य अर्जनों को बढाने की दिशा में अनेक कदम उठाए है । सरकार द्वारा अनुपालित स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम अधिक निर्यातों और अदृश्य उपार्जनों के माध्यम से ऋणों के भुगतान करने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करेंगे ।

(घ) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान अदा किए गए विदेशी ऋण क्रमशः 4466 मिलियन अमरीकी डालर, 4534 मिलियन अमरीकी डालर और 4447 मिलियन अमरीकी डालर थे ।